विनोबा कथावली

■ वर्ष : प्रथम ■ अंक : 8 ■ मार्च 2025

एक शिक्षिका की इच्छाशक्ति का नमूना

रवांदे (अहमदनगर): "हमारे गाँव के स्कूल में दो महिला शिक्षिकाएँ नियुक्त की हैं। ये क्या हमारे बच्चों को पढ़ाएंगी? इनसे नहीं हो पाएगा।" गाँववाले ब्लॉक शिक्षा अधिकारी के पास यह शिकायत कर रहे थे। उस अधिकारी ने इस शिकायत को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा, "अगर मैं एक महिला होकर अधिकारी बन सकती हूँ, तो ये शिक्षिकाएँ आपके बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा सकतीं?"

यह घटना है वर्ष 2011 की। जिस शिक्षिका की नियुक्ति पर यह विवाद हुआ था, वह शिक्षिका हाल ही में एक रेडियो साक्षात्कार में अपनी इच्छाशक्ति की झलक एक सकारात्मक वचन से देती हैं, "बहुत से लोग सोचते हैं कि जिला परिषद स्कूल निजी संस्थानों की बराबरी नहीं कर सकते। लेकिन जब मैं आपको हमारे छोटे से स्कूल के बारे में बताऊंगी, तो आपकी सोच बदल जाएगी।"

यह शिक्षिका, श्रीमती कविता झरेकर, अहमदनगर जिले के विरोबा चौक (संवत्सर) स्थित जिला परिषद प्राथमिक शाला में नियुक्त हुई थी तब गाँववालों को भरोसा नही था कि यह स्कूल कभी उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकती है।"गाँव के लोग शिक्षा के महत्व से अधिक परिचित नहीं थे। अधिकांश छात्र आदिवासी समुदाय से थे, इसलिए अन्य लोग अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतराते थे।"

कविता जी बताती हैं कि बच्चे इसलिए आते थे क्योंकि उन्हें मध्यान्ह भोजन मिलता था। "ज्यादातर बच्चों के लिए यह भोजन का एकमात्र स्रोत था। भूखा बच्चा क्या पढेगा? तीसरी कक्षा के बच्चे भी ठीक से पढ़ नहीं सकते थे। उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। स्कूल का दिया हुआ गणवेष ही एकमात्र कपड़ा होता था, जिसे वे हमेशा पहने रहते थे। गरीबी थी। स्कूल न

आने के बहाने भी ऐसे होते थे—कभी पेन नहीं है, तो कभी कॉपी नहीं है।"

कविता जी और उनकी सहकर्मी ने हार नहीं मानी, जब कि उन्हें रोज़ 10-15 किमी की यात्रा करके स्कूल आना पड़ता था। स्कूल का प्रबंधन पहले बहुत लापरवाह तरीके से होता था। "हम दो शिक्षिकाओं ने अपनी जिम्मेदारियाँ बाँट लीं और धीरे-धीरे सभी विषय, पहनने के तौर-तरीके, असेंबली में अनुशासन, सब कुछ सिखाना शुरू किया। जब मिड-डे मील की रसोइया छुट्टी पर जाती, तो हमें खाना भी बनाना पड़ता था। हम बच्चों के लिए अपने पैसों से खरीदकर अतिरिक्त स्टेशनरी रखते थे, क्योंकि मैं उन्हें किसी भी कारण से स्कूल से दूर नहीं रहने देना चाहती थी।

धीरे-धीरे इसका असर बच्चों के परीक्षा परिणामों और उनके व्यवहार पर दिखने लगा। अन्य माता-पिता भी अपने बच्चों को स्कूल भेजने लगे। संपन्न परिवारों ने भी सराहना की और सहायता व दान दिया। स्कूल में सुधार होने लगा। स्कूल में खेल का मैदान नहीं था, इसलिए विरोबा मंदिर का मैदान खेलों के लिए दिया गया। वार्षिक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। जब कविता जी ने 2018 में स्कूल छोड़ा, तो विद्यार्थियों की संख्या 10 से बढ़कर 30 हो गई थी।

जुलाई में OLF के विनोबा पोस्ट ऑफ द मंथ अवॉर्ड जीतने के बाद, 90.4 FM के साथ एक साक्षात्कार में उनकी यह कहानी सामने आई।

कविता जी अभी जिस स्कूल में है, वहाँ उनके मार्गदर्शन में, वर्तमान स्कूल में खेल, सांस्कृतिक और शैक्षणिक प्रतियोगिताओं में छात्रों की भागीदारी बढ़ी है। 2023 में उनके स्कूल के 10 छात्रों ने मेरिट लिस्ट में जगह बनाई।

इसके अलावा, कविता जी और उनके सहकर्मी रचनात्मक कार्यशालाएँ, वृक्ष दिंडी, सामान्य ज्ञान के सवालों का खेल, आजी-आजोबा दिवस, स्कूल में श्रमदान, छोटे उद्यमियों के हस्तशिल्पों की प्रदर्शनी, खेलों में प्रोत्साहन, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएँ, और अच्छी फिल्में दिखाने जैसी गतिविधियाँ आयोजित करते हैं।

"हम अब सिर्फ एक स्कूल नहीं हैं," कविता जी कहती हैं, "हम सरकारी शिक्षक एक परिवार, एक समुदाय हैं, जो देश के भविष्य का पोषण कर रहे हैं। ग्रामीण शालाएँ बाहर से प्रभावहीन दिख सकती हैं, लेकिन यहाँ के छात्रों की प्रगति इस बात का प्रमाण है कि समर्पण और सही दृष्टिकोण के साथ, एक छोटा सा ग्रामीण स्कूल भी अनगिनत ज़िंदगियों को रोशन कर सकता है।" ■

स्मार्ट शालाएं - एक युवा आईएएस अधिकारी का सपना

"मैं चाहता हूँ कि ज़िला परिषद स्कूलों में प्रवेश के लिए कतार लगें। एक दिन यह ज़रूर होगा। हमारी स्मार्ट शालाएं इस सपने को साकार करेंगी।"

विवेक जॉनसन
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चंद्रपुर

पेज 2

दशकों से अनगिनत चुनौतियों में तपकर निकली अनेक सरकारी शालाएं हैं जो अपने अस्तित्व के सौ वर्ष पूरे कर चुकी हैं, लेकिन आज भी शिक्षा क्षेत्र में उनका योगदान जारी है। टीम विनोबा मानती है कि ऐसे स्कूल भारत के विशाल सरकारी शिक्षा परिवार में किसी बुजुर्ग की तरह हैं जो आज भी अपने निरंतर कार्य से बाकी शालाओं के लिए प्रेरणा का एक अहम स्त्रोत बन गई हैं।

पेज 4, 5, 6

स्मार्ट शालाएं - एक युवा आईएएस अधिकारी का सपना

चंद्रपुर: "मैं चाहता हूँ कि ज़िला परिषद स्कूलों में प्रवेश के लिए लोगों की कतारें लगें। एक दिन यह ज़रूर होगा। हमारी स्मार्ट शालाएं इस सपने को साकार करेंगी।"

चंद्रपूर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी पद पर पिछले तीन वर्ष से कार्यरत श्री विवेक जॉनसन मानते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सरकारी स्कूलों में भी संभव हैं। टीम विनोबा के साथ हाल ही में हुई बातचीत की शुरुवात में ही वे एक सकारात्मक सोच से करते हैं।

जब आपने कार्यभार संभाला तब स्थितियाँ कैसी थी?

हमारे स्कूलों में आउट्कम-बेस्ड लर्निंग की कोई स्पष्ट प्रणाली नहीं थी। आंगनवाड़ियाँ उपेक्षित थी; प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश से पहले की शिक्षा का मूल्यांकन नहीं होता था। आंगनवाड़ियों में भी कुछ पढाना होता हैं, यह बात वहाँ के कर्मचारी थे तो या भूल गए थे या जानते ही नहीं थे।

बच्चों के व्यक्तित्व और कौशल विकास पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। बच्चों को श्रवण यंत्र जैसे विशेष उपकरणों या अनुकूलित शिक्षण पद्धतियों की आवश्यकता थी, जो ज़िले में उपलब्ध नहीं थे। अभिभावक भी इस मामले में अनभिज्ञ थे।

हमने सुना है कि आपके नेतृत्व में बड़ा बदलाव आ रहा है।

आप ये कह सकते हैं कि हमने बदलाव की दिशा में काम शुरू कर दिया है, पूरी ताकत के साथ। हमने 'Chanda Students App' विकसित किया, जिस पर एक लाख से अधिक छात्रों को पंजीकृत कर के उनकी प्रगति को मापने के लिए हर तिमाही में बेसलाइन, मिडलाइन और एंडलाइन सर्वेक्षण किए। कौन से स्कूल, क्लस्टर और ब्लॉक पिछड़ रहे हैं इसका सटीक डेटा हमें इस ऐप से प्राप्त हुआ, जिससे सुधार की दिशा स्पष्ट हो गई। इसीसे हमने (CWSN) दिव्यांग छात्रों का भी अभ्यास किया।

फिर इन छात्रों के लिए मिशन सक्षम के तहत DIET और DHO के विशेषज्ञों की एक टीम बनाई और 1,852 CWSN छात्रों को उनकी आवश्यकताओं के अनुसार यंत्र, फिजियोथेरेपी और शारीरिक गतिविधि सत्र शुरू किए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। अभिभावकों और शिक्षकों को उनकी सहायता के लिए प्रशिक्षित किया गया।

विवेक जॉनसन

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चंद्रपुर

"मैं चाहता हूँ कि ज़िला परिषद स्कूलों में प्रवेश के लिए कतार लगें। एक दिन यह ज़रूर होगा। हमारी स्मार्ट शालाएं इस सपने को साकार करेंगी।"

मिशन अंकुर के तहत 4-6 वर्ष के बच्चों की शिक्षावस्था का मूल्यांकन कर इसे एकीकृत बाल विकास सेवा (ICDS) के साथ जोड़ा गया। आंगनवाड़ी सेविकाओं को प्रशिक्षित किया गया और पहली बार आंगनवाड़ी के बच्चों के लिए बेसलाइन, मिडलाइन और एंडलाइन सर्वेक्षण शुरू किए गए।

लागू किए गए समाधानों की स्वीकार्यता, कैसी थी? क्या-क्या बदलाव आए?

सबसे बड़ा बदलाव तो यह है कि 53 CWSN बच्चे, जो कभी स्कूल नहीं जा पाए थे, अब नियमित स्कूल जा रहे हैं। कई बच्चों ने उठकर बैठना, खड़ा होना और थोड़ा चलना शुरू किया है। मिशन अंकुर की स्वीकार्यता अपेक्षाकृत बहुत कम रही। इसलिए इसका कार्यान्वयन धीमे और चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। इसके पूर्ण परिणाम आने में समय ज़रूर लगेगा, पर यह बेशक प्रारंभिक बाल शिक्षा की एक मजबूत नींव बन रहा है।

पाठ्यक्रम से आगे भी आपकी टीम ने बहुत सारे बदलाव लाने पर काम किया है।

जी, शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायक हर पहलू का हमने गंभीरता से विचार किया। पहले तो हर ब्लॉक में एक स्कूल को अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं, पुस्तकालय, स्वच्छ रसोई तथा डायनिंग एरिया से सुसज्जित कर के 'स्मार्ट शाला' बनाने पर काम शुरू हुआ।

इस वर्ष ऐसी 15 स्कूलों का निर्माण ₹70 करोड़ के बजट से किया जा रहा है। इसी तरह, 100 से अधिक नामांकन वाले स्कूलों में बाल पंचायतों की स्थापना की गई; वित्तीय साक्षरता के लिए 'छात्र बचत बैंक' स्थापित किए गए, जिसके पहले चरण में ही छात्रों ने ₹60,000-₹70,000 की बचत की; 300-400 स्कूलों में पोषण वाटिका बनवाई गई, जिससे बच्चे खेती का तंत्र सीखें और अपने भोजन के लिए ताज़ी सब्जियां भी प्राप्त करें; प्रयोगात्मक शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए 28 'सायन्स पार्क' STEM Lab, Astronomy Lab और Mobile Planetarium शुरू किए गए।

विनोबा कार्यक्रम का योगदान कैसा रहा?

विनोबा ऐप का सब से बड़ा फायदा यह हुआ है कि मैं अपनी जगह से जिले में लागू होने वाली गतिविधियां, उनके परिणाम स्पष्ट आंकड़ों में देख सकता हूँ। अब मुझे अनुमानों पर निर्णय नहीं लेने पड़ते। प्रैक्टिस टेस्ट, शिष्यवृत्ति, JNV और NMMSE के डेटा के लिए अधिकारियों को वाट्सऐप पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। विनोबा ऐप का उपयोग करने की वजह से हमारा बहुत समय बच रहा है।

आनेवाले पाँच साल में दृश्य कैसा रहेगा?

आनेवाले समय में सरकारी स्कूलों की ओर अभिभावक निश्चित रूप से आकर्षित होंगे। हमारे प्रयासों के कुछ परिणाम तुरंत दिख रहे हैं, कुछ समय के साथ साकार होंगे। लेकिन अब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा ज़िला परिषद स्कूलों के हर बच्चे तक पहुंचेगी, क्योंकि अब इसकी नींव रखी जा चुकी है। ■

गड़चिरोली: हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में शिक्षा अधिकारी बाबासाहेब पवार और उप शिक्षा अधिकारी विवेक नाकाडे के हाथों 13 शिक्षकों, 3 संकुल प्रमुखों और 6 स्कूलोंको POM, महावाचन, स्पोकन इंग्लिश और छात्रवृत्ति गतिविधियोंके लिए सम्मानित किया गया। पर टीम विनोबा से चंद्रन रापर्तीवार और गणेश शेंडे उपस्थित थे।

रायपुर: हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में DEO विजय कुमार खंडेलवाल, DMC खेलचंद पटले और अन्य अधिकारियोंने 4 शिक्षकों को POM पुरस्कार से सम्मानित किया, जबकि 6 स्कूलों को उत्कृष्ट 10 वीं और 12 वीं पुरस्कार दिया गया। इस अवसर पर विनोबा टीम से हेमंत साहू और नीलम अहिरवार उपस्थित रहे।

चंद्रपुर: हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में कक्षा 5 के छात्रवृत्ति परीक्षा विजेता, 5 शिक्षकों को POM पुरस्कार, 5 स्कूलों को महावाचन और सामाजिक जागरूकता पुरस्कार, 2 को लाइब्रेरी बैग और 3 संकुल प्रमुखोंको सम्मानित किया गया।इस अवसर पर नूतन सावंत (DyCEO), अश्विनी सोनवणे (EO) और अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

नाशिक: यहाँ आयोजित एक समारोह में 6 संकुल प्रमुखों और 73 शिक्षकोंको विभिन्न श्रेणियों में सम्मानित किया गया, जिनमें POM (15), स्पोकन इंग्लिश चैलेंज (19), स्पेलिंग बी (23), SVEEP (5), लाइब्रेरी बैग (8) और छात्रवृत्ति परीक्षा (3) शामिल हैं। इस अवसर पर ZP CEO आशिमा मित्तल, OLF CEO संजय डालमिया, और कई सरकारी अधिकारी उपस्थित थे।

जलगांव: यहाँ आयोजित एक कार्यक्रम में जलगांव जिले के कलेक्टर श्री आयुष प्रसाद और ZP CEO श्री अंकित कुमारके हाथों 10 POM पुरस्कार विजेता और 4 स्पेलिंग बी विजेता शिक्षकों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और विनोबा टीम की ओर से सचिन ससाणे और संदीप साबळे उपस्थित रहे।

गरियाबंद: हाल ही में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में जिले के 6 शिक्षकोंको 'पोस्ट ऑफ द मंथ' (POM) पुरस्कारसे सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में DEO श्री ए. के. सारस्वत, ADSO श्री श्याम चंद्राकर और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। विनोबा टीम की ओर से प्रोजेक्ट ऑफिसर शुभम पटेलने कार्यक्रम में भाग लिया।

पुणे: यहाँ आयोजित एक भव्य समारोह में कुल 28 शिक्षकोंको POM पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर DIET सीनियर प्रिंसिपल श्री बालकृष्ण वाटेकर, अन्य वरिष्ठ ZP अधिकारी, OLF के COO विश्वजित पवार, क्यूरेशन मैनेजर वैदेही शालू , प्रोजेक्ट ऑफिसर भैरवनाथ गायकवाड और रोहित गरोले उपस्थित रहे।

नागपुर: हाल ही में आयोजित एक कार्यक्रम में नागपुर जिला परिषद के EO (प्राथमिक) सिद्धेश्वर कलूसे ने 5 शिक्षकों को POM, 5 को स्पोकन इंग्लिश गतिविधियों, 1 को महावाचन, और शीर्ष 3 संकुल प्रमुखोंको सम्मानित किया। इस अवसर पर टीम विनोबा की ओर से विशाल डहाट, अतुल भगत और निलेश नागपुरे उपस्थित रहे।

यह वही स्कूल है, जहाँ कभी वह खुद पढ़ा करती थी

गरियाबंद (गरियाबंद): करीब एक दशक पहले तक यह स्कूल 500-600 छात्राओं की चहल-पहल से गूंजता था। सौ साल से भी अधिक पुराना यह स्कूल शुरू में केवल लड़कियों के लिए था। तीन कमरों और एक पुराने बरामदे में सिमटे इस स्कूल की प्राथमिक शाला में जब विनोबा टीम पहुंची, तो इसके लंबे सफर की गवाही देनेवाले कोई खास निशान नजर नहीं आए।

हाल के वर्षों में इसे को-एड स्कूल में बदला गया। इसका जर्जर बॉउन्ड्री वॉल स्कूल को रात के समय असामाजिक तत्वों और नशेड़ियों से बचाने में असमर्थ था।

यहाँ के प्राथमिक कक्षा की शिक्षिका आरती सोनवानी बताती हैं, "जब मैंने 2022 में यहाँ पढ़ाना शुरू किया, बच्चों को स्कूल में लाना एक बड़ी चुनौती थी। मुश्किल से 35 बच्चे थे, वो भी नियमित स्कूल नहीं आते थे।

"अधिकतर अभिभावक या तो निरक्षर थे या शिक्षा को लेकर गंभीर नहीं थे। कुछ अपने बच्चों को जंगलों में फल और लकड़ियाँ बटोरने के लिए ले जाते, तो कुछ उन्हें अपने साथ मजदूरी पर ले जाते। जो बच्चे स्कूल आते भी, उनके कपड़ों और साफ-सफाई की परवाह करनेवाला कोई नहीं होता था।"

प्रधान अध्यापिका श्रीमती संगीता केला के नेतृत्व आरती जी और उनकी सहयोगी शिक्षिका ने इस उदासीनता को रुचि में बदलने की योजना बनाई। हर रोज़ स्कूल खत्म होने के बाद वे गाँव में घर-घर जाकर अभिभावकों को समझाने लगीं। यह अभियान उन्होंने दो साल तक बिना रुके चलाया। शुरुआत में कोई सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। रविवार और छुट्टियों के दिन भी वे उन दरवाजों तक जाती रहीं, जो उनके प्रयासों को नकारने में लगे थे।

धीरे-धीरे उनकी मेहनत रंग लाने लगी। बच्चों की संख्या बढ़ी। लेकिन यह तो बस पहली लड़ाई थी। अब दूसरी चुनौती थी - एक साथ तीन कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाना, वह भी तब, जब अधिकतर बच्चे पढ़ाई में कमजोर थे। पहली, दूसरी और तीसरी कक्षा के बच्चों को एक साथ बैठाकर सिखाना आसान नहीं था। हर कक्षा में अलग अलग क्षमतावाले बच्चे थे। ऐसे में उनकी अनुभवी प्रधान अध्यापिका संगीता जी का मार्गदर्शन मिला। इन शिक्षिकाओं की डी.एड. की ट्रेनिंग भी आई।

"इस समय एक और मदद सामने आई, विनोबा कार्यक्रम के रूप में। विनोबा ने उन्हें अन्य जिलों और राज्यों के शिक्षकों से जोड़ दिया। "उन्हें एहसास हुआ कि इस लड़ाई में वह अकेली नहीं थी। कई शिक्षक इसी स्थिति से जूझ रहे थे, लेकिन अपने तरीकों से रास्ता निकाल रहे थे। विनोबा के माध्यम से उन्हें ऐसी कई नवाचारी शिक्षण पद्धतियाँ देखने को मिलीं।

वे कहती हैं कि पहले वे अपने संकुल (क्लस्टर) से बाहर क्या हो रहा है यह नहीं जान पाती थी। अब वह पूरे राज्य से जुड़े शिक्षकों को देख सकती हैं, उनसे सीख सकती हैं। "मैं चाहती हूँ कि और भी शिक्षक इस प्लेटफॉर्म से जुड़ें। विनोबा ऐप की मदद से शिक्षक कहीं ज़्यादा तेज़ी से विकास कर सकते हैं।"

पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आरती जी खुद इसी स्कूल की छात्रा रही थीं। जब वे यहाँ पढ़ती थीं, तभी सरकारी स्कूलों की स्थिति बिगड़ने लगी थी। शायद तभी उनके मन में यह बात कहीं अंकुरित हो गई थी कि एक दिन इस स्कूल को फिर से उसका पुराना गौरव लौटाना है। किस्मत ने भी जैसे उनके इरादों का साथ दिया और उनकी पहली नियुक्ति इसी स्कूल में हुई, और वह भी प्राथमिक शाला में। उनका मानना है कि अगर एक जिज्ञासु और सीखने के लिए उत्सुक पीढ़ी चाहिए तो उसकी नींव को मजबूत करना होगी। "इसी उम्र से उन्हें मजबूत बनाना मेरा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की ओर हम इसलिए चल पा रहे हैं क्योंकि हमारी संगीता केला मैडम का पूरा सहयोग हमें प्राप्त है।"

शुरुआती दिनों की एक घटना याद करते हुए वे बताती हैं, "एक दिन एक शराबी पिता स्कूल आया और शिकायत करने लगा कि उसके बच्चे को यहाँ कुछ नहीं सिखाया जाता। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि केवल बच्चों को ही नहीं, अभिभावकों को भी शिक्षित करने की ज़रूरत है।"

धीरे-धीरे माहौल बदलने लगा। पढ़ाई के साथ-साथ आरती जी ने अभिभावकों को भी स्कूल से जोड़ना शुरू किया। उन्हें दिखाया कि उनके बच्चे क्या सीख रहे हैं। यह देखकर अभिभावक भी धीरे-धीरे शिक्षा के महत्व को समझने लगे और स्कूल को बेहतर बनाने में हाथ बँटाने लगे। अब वे खुद अपने बच्चों की पढ़ाई को लेकर सतर्क रहने लगे हैं।

आरती जी आत्मविश्वास से कहती हैं, "यह बदलाव की केवल शुरुआत है। आने वाले समय में यह स्कूल और बेहतर होगा। आप देखना, इस स्कूल का पुराना स्वर्णिम दौर एक दिन लौट आएगा।" ■

कनकी का नाम सार्थक करती शिक्षिका – कांचन टंडन

"ये मासूम बच्चे बीज की तरह हैं। शिक्षा के पोषण से ये सुनहरे भविष्य की फसल बनेंगे।"

कनकी (रायपुर): हर शनिवार, कनकी स्कूल के बच्चे उत्साह से अपने कक्षा में इकट्ठा होते हैं। उनकी शिक्षिका, श्रीमती कांचन टंडन, पूरे सप्ताह की गतिविधियों की तस्वीरों का एक वीडियो कोलाज दिखाती हैं-जिसमें वे सीखते, खेलते, रचनात्मक कार्य करते नजर आते हैं। बच्चे खुशी से खिल उठते हैं, जब वे खुद को स्क्रीन पर देखते हैं।

"उन्हें खुद को उस वीडियो में देखना बहुत अच्छा लगता है," कांचन जी कहती हैं, "और उसमें आने के लिए वे पूरे हफ्ते मेहनत करते हैं।"

आज कनकी स्कूल एक खास ऊर्जा से भरा हुआ दिखाई देता है।छात्र पढ़ाई में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं, और माता-पिता भी अब अपने बच्चों की शिक्षा में रुचि लेते हैं। यह स्कूल एक उज्जवल भविष्य की आशा जगाता है।

हालाकि यह स्कूल सौ साल पुराना है, जब कांचन जी पहली बार स्कूल में आईं, तो इस स्कूल की स्थिति चिंताजनक थी। पहली से पाँचवीं कक्षा तक के 86 छात्र थे, लेकिन पढ़ाने के लिए उनके अलावा एक ही शिक्षिका थीं। पाँच स्वीकृत शिक्षकों में से दो का प्रमोशन हो चुका था और तीन को मिडिल स्कूल में स्थानांतरित कर दिया गया था। अधिकांश छात्र गरीब और अशिक्षित परिवारों से थे; कुछ तो अपने बुजुर्ग दादा-दादी के सहारे जी रहे थे।

स्कूल की हालत भी बदतर थी। बच्चे अंधेरे, बिना हवा वाली कक्षाओं में बैठते थे, और कई तो खिड़कियों से कूदकर भाग जाते थे। जिन कमरों का निर्माण पढ़ाई के लिए किया गया था, वे पुराने कबाड़ रखने के काम आ रहे थे।

वह कहती हैं, "सबसे पहले मैंने उन कमरों को साफ करवाया और बच्चों के लिए उपलब्ध करवाया," वे कहती हैं। "अब बच्चे भागते नहीं है। मैंने उन्हें अनुशासन भी सिखाया, जैसे कक्षा से बाहर जाने से पहले अनुमति मांगना। यह एक छोटा सा बदलाव था, लेकिन इससे बड़ा फर्क पड़ा।"

एक और समस्या यह थी कि बच्चों को नया गणवेष मिलने के बावजूद वे पुराना, जीर्ण गणवेष पहनते थे। कई छात्र कॉपी और पेन तक नहीं लाते थे, और हफ्ते भर में ही अपनी कॉपी के पन्ने फाड़कर खत्म कर देते थे। इसलिए कंचन जी ने अपने खुद के पैसे और स्कूल के फंड से अतिरिक्त पेंसिल और रबर रखना शुरू किया।

शिक्षक कम थे इसलिए सभी कक्षाओं को एक साथ पढ़ाना पड़ता था। "इससे सीखने की गुणवत्ता प्रभावित होती है। बच्चे अनियमित पढ़ाई के कारण जल्दी भूल जाते थे। ऊपर से प्रशासनिक काम का दबाव भी रहता था।"

नए शिक्षक नियुक नहीं हो रहे थे, तब कंचन जी स्वयं ही पारिश्रमिक देकर एक अस्थायी शिक्षक नियुक्त करने को तैयार हो गई थी। कई प्रयासों के बाद अब स्कूल में तीन शिक्षक हैं।

उन्होंने बच्चों को पढ़ाई से जोड़ने के लिए नए तरीकों को अपनाया। अपने पहले स्कूल अनुदान से, उन्होंने एक माइक खरीदा ताकि बच्चे सबके सामने खड़े होकर बोलने के लिए प्रोत्साहित हो। अगले साल, उन्होंने एक एलईडी स्क्रीन मंगवाई, जिस पर वे यूट्यूब वीडियो दिखाने लगीं— हस्तकला ट्यूटोरियल, फाउंडेशनल लिटरेसी के पाठ और संगीत व नृत्य के वीडियो भी।

वह बताती हैं, "जब मैं उन्हें कोई पाठ दुबारा दिखाती हूँ और वे पहले ही बोलने लगते हैं, तब पता चलता है कि वे ध्यान से देख और सीख रहे हैं।"

स्कूल प्रबंधन समिति (SMC) की बैठकों और व्हाट्सएप अपडेट्स में, कांचन जी यह वीडियो माता-पिता को दिखाती हैं। "जब माता-पिता अपने बच्चों को अच्छा प्रदर्शन करते देखते हैं, तो उन्हें गर्व होता है। कुछ अभिभावक तो अब घर पर भी बच्चों की प्रैक्टिस करवाने लगे हैं।"

अब भी चुनौतियाँ बनी हुई हैं। कुछ बच्चे अब भी नियमित स्कूल नहीं आते। निजी स्कूलों के बढ़ते प्रभाव से नामांकन संख्या घट रही है। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद, कांचन जी का हौसला कायम है। वे कहती हैं, "शिक्षा सिर्फ किताबों और परीक्षाओं तक सीमित नहीं होती, यह ऐसा वातावरण बनाने की प्रक्रिया है, जहाँ बच्चे खुद सीखने के लिए प्रेरित हों।"

यही विचार लेकर वे बिना रुके एक-एक कदम आगे बढ़ रही हैं। ■

108 वर्ष से निरंतर कार्यरत काटेवाडी जिला परिषद स्कूल

काटेवाडी (पुणे): पुणे जिले के बारामती तालुका में स्थित काटेवाड़ी सिर्फ एक गाँव नहीं, बल्कि शिक्षा और राजनीति की समृद्ध परंपरा का प्रतीक है। इस गाँव की ज़िला परिषद स्कूल न केवल अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता के लिए जानी जाती है, बल्कि इसका सौंदर्य भी मनमोहक है। हरियाली से घिरा विशाल प्रांगण और ज्ञान के उजाले से प्रकाशित यह विद्यालय हर आगंतुक को अपने बचपन की याद ज़रूर दिलाता है।

स्कूल में प्रवेश करते ही केंद्रप्रमुख श्रीमती शाफ़िया तांबोली, मुख्याध्यापिका श्रीमती रानी अण्णा ढम्मे, और शिक्षक संतोष सातपुते व वनिता जाधव से टीम विनोबा की बातचीत हुई। पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों का प्रदर्शन देखकर हम सब चकित रह गए। बातचीत के दौरान स्कूल की स्थापना, ऐतिहासिक यात्रा और विकास पर चर्चा हुई।

सन 1916 में इस स्कूल की नींव रखी गई थी। दशकों की यात्रा के बाद, शिक्षकों की मेहनत, ग्रामवासियों का सहयोग और विद्यार्थियों की सीखने की ललक से स्कूल ने काफी प्रगति की और पूरे क्षेत्र में इसका नाम होने लगा।

लेकिन जैसे-जैसे स्कूल में छात्रों की संख्या बढ़ी, बैठने की जगह कम पड़ने लगी और यह एक गंभीर चिंता का विषय बन गया। ऐसे में गाँव के पूर्व छात्रों ने मदद के लिए हाथ बढ़ाया। साल 2000 में काटे परिवार ने स्कूल के लिए ढाई एकड़ जमीन दान कर दी, और पवार परिवार ने प्रशासन से आवश्यक अनुदान प्राप्त करने में मदद की। इससे नए भवन का निर्माण संभव हो सका और स्कूल का गुणवत्ता में सुधार लाने की ओर एक और कदम बढ़ा।

विद्यालय में समय-समय पर कई अभिनव योजनाएँ शुरू की गईं, जिनमें स्वच्छता अभियान सबसे प्रमुख था। शिक्षकों, ग्रामवासियों और विद्यार्थियों के संयुक्त प्रयासों से इस अभियान को सफलता मिली और 2007 में काटेवाड़ी स्कूल को राज्यस्तरीय 'माझी शाळा - स्वच्छ शाळा' पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

लेकिन फिर काटेवाड़ी स्कूल के सामने एक नई चुनौती खड़ी हो गई। गाँव में इंग्लिश मीडियम की निजी स्कूलें खुलने लगीं। कई अभिभावक यह मानने लगे कि उनके बच्चे अगर इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, तो ही वे अंग्रेज़ी में अधिक कुशल होंगे। कई विद्यार्थियों ने निजी स्कूलों की ओर रुख कर लिया।

इस स्थिति का सामना करने के लिए मुख्याध्यापिका रानी ढम्मे और शिक्षक काटे सर ने रणनीति तैयार की। उन्होंने कहा, "गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केवल अंग्रेज़ी भाषा पर निर्भर नहीं करती, बल्कि शिक्षण की पद्धति और समर्पण पर निर्भर करती है।" इसके बाद, शिक्षकों ने गाँव के प्रत्येक परिवार से संपर्क कर उन्हें समझाया कि उनकी स्कूल में शिक्षा केवल पारंपरिक पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ छात्रों के संपूर्ण विकास पर ध्यान दिया जाता है।

इस उद्देश्य को साकार करने के लिए स्कूल में विभिन्न नवाचार किए गए। छोटे बच्चों के लिए आंगनवाड़ी कार्यक्रमों में स्वादिष्ट भोजन के साथ बालगीतों पर नृत्य, चित्रकला, और गर्मी की छुट्टियों में विशेष शिविरों का आयोजन किया गया। प्राथमिक और माध्यमिक के छात्रों के लिए ज़िला परिषद, प्रशिक्षण संस्थानों और ओपन लिंक्स फाउंडेशन जैसी समाजसेवी संस्थाओं के सहयोग से विदेशी भाषा शिक्षण, स्पोकन इंग्लिश सत्र, 'आनंददायी शनिवार' यानि खेल और रचनात्मक गतिविधियों का दिन, वाचन और विषय केंद्र, 100 पौधारोपण अभियान, चित्रकला और भाषण प्रतियोगिताएँ, लोकनृत्य एवं लेज़ीम स्पर्धाएँ आयोजित की गईं।

इन प्रयासों के फलस्वरूप, काटेवाड़ी स्कूल ने ज़िला स्तर पर नृत्य और लेज़ीम प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया और 'माझी शाळा - सुंदर शाळा' पहल में तालुका स्तर पर प्रथम स्थान हासिल किया। यह स्कूल फिर से अपनी गुणवत्ता और नवाचारों के कारण प्रसिद्ध हो गई, और छात्र संख्या स्थिर बनी रही।

ढम्मे मैडम कहती हैं, "हमारा उद्देश्य सिर्फ बच्चों को शिक्षित करना नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व का समग्र विकास करना है।"

108 वर्ष पुराना काटेवाड़ी स्कूल, किसी आदर्श बुजुर्ग की तरह एक मिसाल बन चुका है, जहाँ शिक्षा को सिर्फ किताबों तक सीमित न रखकर जीवन कौशल से जोड़ा गया है। इस विद्यालय ने दिखा दिया है कि जब शिक्षक, अभिभावक और समाज एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। ■

'विनोबा ऐपने मेरी फ़ेसबुक रील्स की आदत छुड़वा दी'

टाकली ढोकी (धाराशिव) : आज के दौर में, जब हर उम्र के लोग सोशल मीडिया रील्स में उलझे हुए हैं और घंटों बेकार की सामग्री देखने में बिता रहे हैं, वहीं धाराशिव जिले के ज़िला परिषद स्कूल, टाकली ढोकी में कार्यरत शिक्षक श्री लहु सुरवसे का यह दावा इस आम धारणा को गलत साबित कर देता हैं। वे कहते हैं कि विनोबा ऐप का उपयोग शुरू करने के बाद उनकी फेसबुक रील्स स्क्रॉलिंग की उनकी आदत छूट गई।

हम से बातचीत की शुरुआत में ही लहु जी कुछ मार्मिक कहते हैं, "लोग यह मानते हैं कि वे सिर्फ़ मनोरंजन के लिए सोशल मीडिया देखते हैं। लेकिन इंसान हमेशा ज्ञान और नई जानकारी की तलाश में रहता है। इसीलिए हमें सोशल मीडिया आकर्षित करता है। किन्तु इन प्लाटफॉर्म्स पर कई भटकाव भी होते हैं जो कि व्यावसायिक हितों की वजह से आते हैं।"

लहु जी का मानना है कि शिक्षकों के लिए एक ऐसा टेक्नॉलजी प्लेटफॉर्म बेहद ज़रूरी था, जहां केवल शिक्षा पर चर्चा हो। उनके अनुसार फेसबुक पर बिताया गया 70% समय व्यर्थ जाता है। "वही समय अगर मैं विनोबा ऐप पर लगाऊं, तो शिक्षक के रूप में मेरा विकास होता है।"

2016 में लहु जी यहाँ आए, तब वहाँ के शिक्षकों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा बच्चों को स्कूल से जोड के रखने में सफल तो हो रहे थे, पर बच्चे तब भी अध्ययन में रुचि नहीं ले रहे थे। उन्हें लगा कि छात्रों को पढ़ाई से जोड़ने के नए तरीके अपनाने होंगे।

"अभिभावकों को अंग्रेज़ी भाषा का ज़्यादा आकर्षण होता है, इसलिए मैंने पहले स्पोकन इंग्लिश सिखाने पर ध्यान केंद्रित किया। पहले तो उन्हें कक्षा में सबके सामने पढ़ने को कहा। फिर उन्हें एक दूसरे से अंग्रेज़ी में संभाषणके लिए प्रोत्साहित किया। उन्हें पुरस्कार देने शुरू किए। जब बच्चों को महसूस हुआ कि उनके प्रयासों की सराहना हो रही है, तो वे और मेहनत करने लगे।"

धीरे-धीरे उन्होंने यह तरीका गणित और विज्ञान में भी अपनाया। जल्दी ही स्कूल की अच्छी पढ़ाई की चर्चा होने लगी, जिससे नए विद्यार्थी भी आकर्षित हुए। अब स्कूल में नामांकन संख्या 65 से बढ़कर 100 के पार हो गई है। दो साल पहले लहु जी ने बच्चों के वीडियो विनोबा ऐप पर अपलोड करने शुरू किए,

और 'पोस्ट ऑफ द मंथ' के पुरस्कारों को बच्चों में बाँट दिए। इससे बच्चों का उत्साह और बढ़ गया और वे बेहतर प्रदर्शन करने लगे।

"फेसबुक रील्स देखने की आदत से छुटकारा पाने के बाद मैं अपना अधिकतर समय विनोबा ऐप पर बिताता हूँ। मुझे यहाँ सीखने के लिए बहुत कुछ मिलता है, जिसे मैं अपने स्कूल में लागू करता हूँ और उसके अच्छे परिणाम भी पाता हूँ।"

वे कहते हैं कि इस ऐप पर स्कूलों में आनेवाली चुनौतियों के संदर्भ में अन्य शिक्षकों से एक सार्थक संवाद स्थापित हो रहा है। लहु जी महाराष्ट्र राज्य आदर्श शिक्षक संघ के जिला महासचिव भी हैं, इसलिए उन्हें समय-समय पर रिकॉर्ड, परिपत्र और आँकड़ों की जरूरत होती है। वे कहते हैं, "विनोबा पर हर जानकारी व्यवस्थित होती है, जिससे ज़रूरी आँकड़े तुरंत मिल जाते हैं।"

शिक्षकों के साथ-साथ प्रशासनिक अधिकारी भी इस ऐप पर सक्रिय हैं, जिससे वे सीधे देख सकते हैं कि कौन-कौन सी शैक्षिक गतिविधियाँ हो रही हैं। "वे हमारी मेहनत को लगातार देख रहे हैं। अब हमारा काम अनदेखा नहीं होता। विनोबा ने शिक्षा तंत्र में इस पारदर्शिता को संभव बनाया है।"

लहुजी की यह बात विनोबा कार्यक्रम का लक्ष्य सार्थक करती है। उनका यह वचन इस कार्यक्रम को सारांशित करता हैं, "विनोबा से पहले मैं अकेले एक ज़िला परिषद स्कूल के बच्चों की ज़िंदगी संवारने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब मैं पूरे देश के विशाल शिक्षक समुदाय का हिस्सा हूँ। पहले मैं सिर्फ़ एक बूंद था, अब मैं समंदर बन गया हूँ।" ■

गिनती सीखो

सीखो आकृति खेल खेल में पढ़ लो।
गणित लगेगा सरल तुम्हें
तुम इसको मन में गुन लो
लिखना अभी नहीं है तुमको
बस आकार पहचानो
गोल है रोटी तिकोन पराठा
दरवाजा आयत कहलाए
खिड़की वर्गाकार
अभी इन्हीं को देखो, सीखो
खूब मजे लो यार।
चंदा गिनलो सूरज गिनलो
दिन सप्ताह के सात
तारों को भी गिनकर देखो
मजेदार यह खेल ।।
महीनों के भी नाम गिनो तुम
होते पूरे बारह
साथ में अपनी उमर बता
तीन पांच या बारह
FL N के संग सीखो तुम
पढ़ना संग संग गुनना ।
आएगा तुमको है मजा
जब सीखोगे पहाड़ा
दो से लेकर बारह तक
खेल खेल में यारा।।

डॉ. प्रज्ञा सिंह
शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला हनोदा
ब्लॉक, जिला दुर्ग

महाराष्ट्र में नया शैक्षणिक वर्ष 1 अप्रैल से

शिक्षा विभाग ने की तैयारी तेज़

महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने आगामी शैक्षणिक वर्ष 2025-26 से राज्य के स्कूलों में 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू करने के निर्णय को लागू करने की तैयारियां तेज़ कर दी हैं।

स्कूल शिक्षा मंत्री पंकज भोंयर ने आश्वस्त किया है कि इस निर्णय को लेकर पूरी स्पष्टता है, और जिला तथा तालुका स्तर पर अधिकारी समन्वय कर रहे हैं ताकि यह परिवर्तन सहज रूप से लागू हो सके।बालभारती में आयोजित समीक्षा बैठक में भोंयर ने बताया कि इस वर्ष पहली कक्षा की पाठ्यपुस्तकें सीबीएसई (CBSE) पाठ्यक्रम के अनुसार तैयार की जाएंगी, और धीरे-धीरे उच्च कक्षाओं में भी यह बदलाव लागू किए जाएंगे। उन्होंने यह भी घोषणा की कि 'पीएम श्री' स्कूलों की तर्ज पर 'सीएम श्री' स्कूल शुरू किए जाएंगे, जिनका उद्देश्य शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार लाना है।इसके अलावा, सरकार विद्यानिकेतन स्कूलों में 'आनंद निवासी गुरुकुल' शुरू करने की योजना बना रही है, जहां कला, खेल और संगीत में विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा।

साथ ही, सरकार एक नया कानून भी बना रही है, जिसका उद्देश्य पूर्व-प्राथमिक शिक्षा को नियमित करना और RTE के अंतर्गत फीस प्रतिपूर्ति से जुड़ी चिंताओं का समाधान करना है।

79 देशों में स्कूलों में स्मार्टफोन प्रतिबंधित, भारत में अब भी कोई स्पष्ट नीति नहीं

दुनिया भर में स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग पर बहस जारी है, लेकिन भारत में इस संबंध में अब तक कोई विशेष कानून नहीं बनाया गया है। यूनेस्को (UNESCO) की रिपोर्ट के अनुसार, 79 शिक्षा प्रणालियों ने स्कूलों में स्मार्टफोन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, क्योंकि कई देशों का मानना है कि यह सीखने की प्रक्रिया और बच्चों की निजता पर नकारात्मक प्रभाव डालता है।

2023 के अंत तक 60 देशों ने विशेष कानून या नीतियों के माध्यम से स्कूलों में स्मार्टफोन पर रोक लगा दी थी। 2024 के अंत तक 19 और देश इस सूची में शामिल हुए।

चीन के झेंगझोउ शहर में प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में स्मार्टफोन पर प्रतिबंध को और सख्त कर दिया गया है।

फ्रांस के माध्यमिक विद्यालयों में पहले से लागू प्रतिबंध के साथ "डिजिटल ब्रेक" की सिफारिश की गई है, जिससे छात्रों को तकनीकी उपकरणों से दूर रहने का अवसर मिले। अमेरिका: 50 में से 20 राज्यों ने स्कूलों में स्मार्टफोन उपयोग को लेकर सख्त नियम लागू किए हैं।

इन देशों का कहना हैं कि सिर्फ पढ़ाई पर असर ही नहीं, बल्कि कई एप्लिकेशन अनावश्यक डेटा संग्रह करके छात्रों की गोपनीयता का उल्लंघन भी कर रही हैं।

2023 में सिर्फ 16% देशों ने शिक्षा में डेटा गोपनीयता को कानूनी रूप से सुनिश्चित किया था। वहीं, कोविड-19 के दौरान उपयोग की गई 163 शिक्षा तकनीक उत्पादों में से 89% बच्चों की निगरानी कर सकते थे।

ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग (GEM) रिपोर्ट 2023 के अनुसार, कुछ तकनीक कुछ परिस्थितियों में शिक्षा को मदद कर सकती है, लेकिन उसका अधिक उपयोग या अनुचित उपयोग नुकसानदायक हो सकता है।

एक अध्ययन के अनुसार, यदि छात्र एक बार ध्यान भटका दें, तो उन्हें फिर से पढ़ाई पर केंद्रित होने में 20 मिनट तक लग सकते हैं। बेल्जियम, स्पेन और यूनाइटेड किंगडम में स्मार्टफोन प्रतिबंध के बाद छात्रों के सीखने के परिणामों में सुधार देखा गया।

भारत में स्कूलों में स्मार्टफोन उपयोग पर अब तक कोई राष्ट्रीय स्तर की नीति नहीं बनी है। हालांकि, कई स्कूल और राज्य सरकारें अपने स्तर पर नियम बना रही हैं, लेकिन अब भी एक सख्त और स्पष्ट कानून की आवश्यकता बनी हुई है।

CBSE 2026 बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार कराने पर विचार

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) साल 2026 से कक्षा 10 वीं और 12 वीं की बोर्ड परीक्षाएं साल में दो बार कराने पर विचार कर रहा है। जल्द ही इस प्रस्ताव को सार्वजनिक किया जाएगा ताकि सभी संबंधित पक्षों से प्रतिक्रिया ली जा सके।

यह बदलाव राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 2020 के तहत लाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाना और छात्रों के तनाव को कम करना है। इस नई प्रणाली से छात्रों को अपने अंकों में सुधार करने का अतिरिक्त अवसर भी मिलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 18 फरवरी को मंत्रालय और CBSE के अधिकारियों के साथ इस पर विस्तार से चर्चा की। प्रस्ताव के तहत, शैक्षणिक सत्र 2025-26 से छात्रों को 10 वीं और 12 वीं की बोर्ड परीक्षाओं में दो बार बैठने की सुविधा दी जाएगी।

कूट प्रश्न 8

A + B = 10
B + C = 8
A + C = 12

What are the values of A, B and C?

शिक्षा क्षेत्र के बजट में 6.22 प्रतिशत की वृद्धि

केंद्र सरकार के वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग को अब तक का सबसे अधिक ₹78,572 करोड़ का बजट मिला है, जो पिछले बजट अनुमानों की तुलना में 7 प्रतिशत अधिक और 2024-25 के संशोधित अनुमानों की तुलना में 16.28 प्रतिशत अधिक है।

शिक्षा से जुड़ी योजनाओं के बजट में भी उल्लेखनीय वृद्धि की गई है—समग्र शिक्षा योजना को ₹4,240 करोड़ अधिक (11 प्रतिशत वृद्धि); पीएम-पोषण योजनाको ₹2,500 करोड़ अधिक (25 प्रतिशत वृद्धि); और पीएम-श्री योजना को ₹3,000 करोड़ अधिक (66 प्रतिशत वृद्धि) है। इसके अलावा, सरकार अगले पांच वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स (ATL) स्थापित करेगी ताकि छात्रों में नवाचार को बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही, भारतनेट परियोजना के तहत अगले तीन वर्षों में सभी सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को ब्रॉडबैंड से जोड़ा जाएगा। विशेषज्ञों के अनुसार, इससे डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल को लागू करने में तेजी आएगी और छात्रों के लिए पाठ योजनाओं की पहुंच आसान होगी।

कूट प्रश्न 8 का उत्तर: A=7, B=3, C=5

OLF का हाई-टेक विनोबा कार्यक्रम सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए, जिला प्रशासन के साथ मिलकर शिक्षकों की सहायता करता है, उन्हें पुरस्कृत और प्रोत्साहित करता है। साथ ही अभिनव उपक्रमों को लागू करने की क्षमता बढ़ाने पर काम करता है।

ओपन लिंक्स फाउंडेशन
बंगलो नं. 3, तात्या टोपे सोसायटी, शिवरकर गार्डन के सामने, पुणे-411040
संस्थापक: संजय डालमिया ■ सह संस्थापक: रीना डालमिया
संपादक: अमोल मावकर